NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

NCL

Regd Off : Greens Villey City, Housing Board Colony, Boriyakala,
Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711 E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

No. NCL/HO/Dep-4/FC-EDS/2024/1544 **Date: 08/11/2024**

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दंतेवाड़ा वनमंडल,
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

विषय – Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s NMDC-CMDC Limited for non-forestry use of 682.2722 ha (570.100 ha inside lease and 112.1722 ha outside lease) forest land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 Mine in Dantewada Forest Division, South Bastar, Dantewada District in the State of Chhattisgarh– **Submission of EDS reply regarding. (Reg.No. FP/CG/MIN/146694/2021)**

संदर्भ – 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 07.03.2024.
2. एनसीएल का पत्र No. NCL/HO/Dep-4/FC/2024/1462 दिनांक 22/04/2024
3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि../3320 दंतेवाड़ा, दिनांक 16.05.2024.
4. एनसीएल का पत्र No. NCL/HO/Dep-4/FC-EDS/2024/1469 दिनांक 20/05/2024
5. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि../4018 दंतेवाड़ा, दिनांक 25.05.2024.
6. एनसीएल का पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/FC/2024/1538 दिनांक 30/10/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप –4 के वन भूमि स्वीकृति के संबंध में 26 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी, जिसके संदर्भ में .एनसीएल द्वारा पत्र दिनांक 22/04/2024 के माध्यम से समुचित जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। तदोपरांत आपके द्वारा सदर्भ क्रमांक –5 के माध्यम से तीन बिन्दुओ पर अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी।

उपरोक्त वर्णित प्रकरण में इस पत्र के माध्यम से अपेक्षित तथ्यात्मक जानकारी संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

सादर।

भवदीय

प.च. नाईक 08/11/24

(पद्मनाभ नाईक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Sl. No.	EDS Description	Reply of the project Proponent
1.	बिन्दु क्रमांक :— (ii) उक्त बिन्दु मे आपके द्वारा एन.एम.डी.सी. बचेली एवं किरन्दुल में ICFRE Dehradun के द्वारा अध्ययन करना बतलाया गया है, जबकि ICFRE Dehradun के द्वारा निक्षेप क्रमांक–5, 10, 11, एम.एल., 14 एम.एल. एवं 14 एन.एम.जेड़. में स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के शर्तों के उल्लंघन के एवज मे ICFRE Dehradun के द्वारा अध्ययन कराया गया है। भारत सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति अनुसार उक्त बिन्दु में Maximum Permissible Production Level के संबंध में अध्ययन की जानकारी चाही गई है जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र सतत् रहते हुये उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को भी कोई नुकसान न हो। संदर्भित पत्र–5 के माध्यम से आपके द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक है। अतः सही जानकारी से अवगत करावें।	It may be noted that no study report is available either with user agency or with the Chhattisgarh State Govt on the matter of maximum permissible production level in the Bailadila Area. However, as the Environmental Clearance process involves comprehensive evaluation of the potential environmental impacts of a mining project and the adequacy of the proposed mitigation measures thereof, hence, quantum of the iron ore to be produced must be regulated by the terms and conditions of the Environment Clearance.
2.	बिन्दु क्रमांक :— (viii) उक्त बिन्दु मे प्रस्तावित खनन क्षेत्र के दोनो ओर ट्री–फर्न प्रजाति विद्यमान है। जिस पर खनन गतिविधियों के कारण भविष्य मे नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना है, जिसका अध्ययन ICFRE Dehradun से कराने हेतु आपके द्वारा शुल्क जमा किया गया है, जिसे ICFRE Dehradun को प्रेषित किया जा रहा है।	It has been informed vide letter No. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-305/2593 dtd. 06.11.2024 by the office of APCCF(LM) ***(Copy attached as Annexure-1)*** that ICFRE, Dehradun has submitted its draft report on "study of Bailadila Iron Ore Deposit-4 Mine of NMDC-CMDC Limited for ascertaining the safe distance from the existing tree-fern Habitat for carrying out mining activities and infrastructure development". Forest Deptt is requested for early finalization of the ICFRE report.
3.	बिन्दु क्रमांकः— (xii) उक्त बिन्दु में भारत सरकार, द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023, 13 (1) के अनुसार दुगुने वन भूमि मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए मान्य नहीं किया जा रहा है। अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि चयन कर, के.एम.एल. फाईल, वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डी.जी.पी.एस. मानचित्र के साथ संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	Present proposal of the CA on degraded Forest Land should be accepted as per the provision given under sub Rule 13 (4) (a) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. In continuation to our previous clarification, following may please be noted: - **i.** MoEF&CC, GoI vide letter dated 09.09.2024 clarified that "As per the provisions given undersub rule (4) of rule 13, the NMDC proposal in Chhattisgarh is eligible for raising CA over degraded forest land subject to conditions prescribed therein. The proposal for raising compensatory afforestation over degraded forest land should be last option after exhausting the availability of all other eligible non-forest/revenue forest land." ***(Copy attached as Annexure-2)***

प.च. नायक 08/11/24

		ii. MoEF&CC, GOI vide Gazette Notification dated 20.09.2024 amended the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 that " The entries against serial number 3, under the brackets and words "(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)" shall be omitted." ***(Copy attached as Annexure-3)***

प.चं.नायक 08/11/24

Annexure-1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–305/2593 रायपुर, दिनांक 06/11/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दंतेवाडा वनमंडल दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़

विषयः– **'Study of Baildila Iron Ore Deposit-4 Mine of NMDC-CMDC Limited for ascertaining the safe distandce from the existing Tree Fern Habitat for carrying out mining axtivities and infrastrucature development'** की मसौदा अध्ययन रिपोर्ट जमा करने के संबंध में।

संदर्भः– सहायक महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून पत्र क्रमांक/1-138/2024-ADG (EM)/ Deposit-4 Mine/NMDC/ICFRE/1358 दिनांक 29-10-2024

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.03.2024 के बिन्दु क्रमांक – viii के अनुक्रम में आई.सी.एफ.आर.ई देहरादून के पत्र दिनांक 29.10.2024 द्वारा 'Study of Baildila Iron Ore Deposit-4 Mine of NMDC-CMDC Limited for ascertaining the safe distandce from the existing Tree Fern Habitat for carrying out mining axtivities and infrastrucature development' से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट आपके अवलोकन एवं सुझाव हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः आई.सी.एफ.आर.ई देहरादून द्वारा प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट की प्रति अवलोकन एवं सुझाव हेतु संलग्न प्रेषित है। अध्ययन रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन/सुझाव (यदि कोई हो) तो इस कार्यालय को शीघ्रअतिशीघ्र अवगत करावें ताकि भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद देहरादून को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–305/2594 रायपुर, दिनांक 06/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **सहायक महानिदेशक**, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पो.ओ. न्यू फारेस्ट, देहरादून, 248006 (उत्तराखण्ड)
2. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी., ग्रीन वेली सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

479- Letter Minig 2024

पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग
Environment Management Division
विस्तार निदेशालय
Directorate of Extension
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
पो0 ओ0 न्यूफॉरेस्ट, देहरादून 248 006
P.O. New Forest, Dehradun-248006 (Uttarakhand)

No.1-138/2024-ADG(EM)/ Deposit-4 Mine/NMDC/ICFRE/1358 दिनांक: 29.10.2024

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सैक्टर –19, नॉर्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्पलैक्स
नवा रायपुर, अटल नगर – 492 002
छत्तीसगढ़

ईमेल: apccf-lm.cg@gov.in

विषय : 'Study of Bailadila Iron Ore Deposit - 4 Mine of NMDC-CMDC Limited for ascertaining the safe distance from the existing Tree Fern Habitat for carrying out mining activities and infrastructure development' की मसौदा अध्ययन रिपोर्ट जमा करने के संबंध में।

सन्दर्भः आपका कार्यालय वर्क ऑर्डर नं0 भू–प्रबंध/खनिज/331–305/1242 दिनांक 22.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा 'Study of Bailadila Iron Ore Deposit - 4 Mine of NMDC-CMDC Limited for ascertaining the safe distance from the existing Tree Fern Habitat for carrying out mining activities and infrastructure development' से संबधित कार्योपरान्त मसौदा अध्ययन रिपोर्ट आपके अवलोकन एवं सुझाव (यदि कोई हो) हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन/ सुझाव (यदि कोई हो) हो तो कृपया इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करें, ताकि फाईनल अध्ययन रिपोर्ट की सॉफ्ट एवं हार्ड प्रति आपके कार्यालय को भेजी जा सकें।

आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(डा0 ए0 एन0 सिंह) 29/10/24
सहायक महानिदेशक (प्र.प्र.)

प्रतिलिपिः उपमहानिदेशक (विस्तार), विस्तार निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Annexure-2

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
*****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh Road, Aliganj,
New Delhi - 110003.

Dated: 9th September, 2024

To,

The Addl Chief Secretary (Forests),
Governemnt of Chhattisgahr
Atal Nagar, Nava Raipur

Sub: Clarifications sought by the Government of Chhattisgarh on the various provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 – reg.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter no. 5-20/2007/10-2 (part) dated 2.08.2024, Letter No. 5-29/2021/10-2 dated 6.08.2024, letter no. DO No. 5-39/2023/10-2 dated 26.07.2024, letter No. 5-29/2021/10-2 dated 15.07.2024 and letter No. 5-20/2007/10-2 dated 23.07.2024 on the above subject and to say that the clarifications on the issues raised in the aforementioned letters are enclosed herewith.

Yours faithfully,

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Chhattisgarh, Nava Raipur
2. Nodal Officer (Van Sanrakshan Evam Samvardhan), O/o PCCF (HoFF), Government of Chhattisgarh, Nava Raipur with a request to revisit the proposal, as referred by the Government of Chhattisgarh
3. The Dy DDG (Central), MoEF&CC, Regional Office Nagpur/Sub-Office, Nava Raipur
4. Guard File.

Clarifications on the issues referred by the Government of Chhattisgarh

Reference received from Chhattisgarh	Issues referred by the Government of Chhattisgarh	Comments of Forest Conservation Division
letter No. 5-20/2007/10-2 (part) dated 2.08.2024	i. In case of proposals located in the LWE Districts where 'in-principle' approval has already been granted by the State Government before 1.12.2023 under the General Approval, the final approval in such cases is to be granted by whom i.e. whether by the State or by Central Government. ii. In respect of 12 categories of proposals pertaining to the public utilities projects, located in the LWE districts, whether the State Government can grant permission for proposals involving area up to 5 ha.	i. Provisions of General Approval in this regard is not in vogue and the proposals already granted 'in-principle' approval under the erstwhile regimes of General Approval are to be processed and approved as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 i.e. final approval in such cases is to be granted at the level of Regional Office of the MoEF&CC. Compliance may accordingly, be ensured by the State Government. ii. In accordance with the provisions of the notification dated 29.11.20223 issued under sub section (3) of section 1A of the Van (Van Sanrakshan Evam Samvadhan) Adhinyam, 1980, the State Government can grant permission, in respect of 12 categories of public utility projects located in the LWE districts, involving area up to 5 ha.
DO No. 5-39/2023/10-2 dated 26.07.2024	Applicability of raising compensatory afforestation over degraded forest land in respect of NMDC proposals in Chhattisgarh	Certain relaxation of raising the compensatory afforestation over degraded forest land has been provided to the Central Public Sector Undertaking in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. As per the provisions given undersub rule (4) of rule 13, the NMDC proposal in Chhattisgarh is eligible for raising CA over degraded forest land subject to conditions prescribed therein. **The proposal for raising compensatory afforestation over degraded forest land should be last option after exhausting the availability of all other**

		eligible non-forest/revenue forest land.
Letter No. 5-29/2021/10-2 dated 15.07.2024	Approval dated 12.04.2022 restricting the felling of trees within the 30 meters of RoW instead of proposed 45 meters. Said approval was subsequently, on a request made by the user agency, modified on 2.12.2022 stipulating the condition that block plantation of 10 times trees to be felled in the RoW beyond 30 meter will be carried put in the nearby degraded forest land. Additional condition of raising avenue plantation of 10 times of trees felled in the RoW of 30 meters has also been stipulated in the said amended approval along with a condtion that henceforth all such plantation will be carried out by the State Forest Department at the cost of user agency. Compensatory afforestation in lieu of diversion of 228.0425 has been stipulated over double degraded forest land (457 ha) for which the user agency has already deposited the compensatory levies. In light of the above, the additional condition of raising 10 times of trees falling in the RoW beyond 30 meters and 10 times trees falling beyond 30 meters does not seem to be appropriate.	Specific conditions in the approval granted to a proposal are stipulated based on examination of proposal by the REC on merits. However, as the compensatory afforestation over double degraded forest land has already been stipulated, the rationale for stipulating the additional condition of afforestation of 10 times trees may be reconsidered by the Regional Empowered Committee.

Letter No. 5-29/2021/10-2 dated 6.08.2024	Extension of Working Permission beyond 2 years in respect of proposal involving diversion of 228.0425 ha granted 'in-principle' approval. i. Stage-I approval was granted on 12.04.2022 and 4.07.2023 ii. Working permission was granted by the State on 25.08.202 to 24.08.2023 iii. Working permission was extended 5.07.2023 to 4.07.2024 by the State. iv. Working permission requested for further period from 25.08.2024 to 25.08.2025	As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, the working permission , after grant of 'in-principle' approval and deposition of compensatory levies by the user agency can be granted by the State Government for a period of one year. The authorities in the State Government are not authorized to extend the working permission beyond a period of one year. The working permission beyond a period of one year can be extended up to another one year by the REC/Advisory Committee, after having satisfied with the progress made by the user agency in compliance of condition stipulated in the approval. The relevant guidelines, as given under para 11.1 of Chapter-11 of Consolidated Guidelines are reproduced as under: *The special provisions allowing the State Governments/Union territory Administrations for tree cutting and commencement of work of linear projects after payment of compensatory levies, can be extended for a further period of one more year, if the Advisory Committee or the Regional Empowered Committee, as the case may be, is satisfied that user agency had made serious efforts to comply with the compliance in "In-Principle' approval and the user agency has submitted an undertaking to obtain 'Final' approval within the period of 2 years from the date of issue of 'in-principle' approval.*
Letter No. 5-20/2007/10-2 dated 23.07.2024	Refresher training session on PARIVESH	The Ministry has recently invited interests from the various States/UTs to organize training session on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)

		Adhiniyam, Rules and PARIVESH 2.0. Ministry has been conducting such training sessions regularly and it can be organized for Chhattisgarh also in the second week of September, 2024.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257289
CG-DL-E-20092024-257289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

G.S.R. 582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely : —

"Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis".

3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —

(i) The entries against serial number 2, under the brackets and words "(*This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.*)" *shall be omitted;*

(ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words "(*This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)*" shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.